

चीन खुले दिल और मुक्त हाथों से डॉक्टर, इंजीनियर व साइंटिस्टों का स्वागत कर रहा है

इससे भारत को दोहरा खतरा है, पहले तो जल्दी ही चीन अमेरिका को पछाड़कर विश्व की नम्बर वन ताकत बन सकता है, दूसरे एशिया के सामरिक संतुलन में चीन अब भारत से बेहिसाब भारी पड़ जायेगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 सितंबर। डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा एच-1 बी वीजा के लिए लगाई गई बहुत ऊंची फीस भारत के लिए गंभीर सिरदर्द है। इसका असर केवल भारत के आईटी सेक्टर और अमेरिका को होने वाले सेवा निर्यात पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह भारत के लिए समग्र सुरक्षा परिवेश और रणनीतिक-कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी बड़ी चिंता है।

अन्य बातों के अलावा, अगर चीन अमेरिका से निकल रही बेहतरीन और शीर्ष प्रतिभाओं का अच्छा हिस्सा अपने देश में लाने में कामयाब हो जाता है, तो वह कम समय में अमेरिका पर अपनी तकनीकी रक्षा बहुत को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल कर पाएगा। यह केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि भारत

■ इस दौड़ में चीन को दो बातों से मदद मिल रही है, पहली शीर्ष नेतृत्व (राष्ट्रपति शी जिनपिंग) स्वयं आगे बढ़कर स्वागत कर रहे हैं। दूसरी चीन के पास अथाह धन है, इसे फलीभूत करने के लिए। टॉप साइंटिस्ट को लुभाने के लिए चीन 5-5 लाख डॉलर का वार्षिक पैकेज ऑफर कर रहा है।

■ चीन के इस प्रयास को सफलता इसलिए भी मिल रही है, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान (इन्स्टीट्यूट) पहले से ही विद्यमान हैं, इन साइंटिस्टों को एजार्ब करने के लिए।

■ इसकी तुलना में भारत में कुछ संस्थाएँ हैं और धन भी है, किन्तु विदेश में स्थित इस टैलेंट को लुभाने के लिए संख्या में बहुत कम हैं।

■ इस प्रकरण में एक और समस्या है कि इन भारतीय संस्थाओं में पहले से आधिपत्य जमाये लोग नये आने वालों के पैर आसानी से जमने नहीं देना चाहते।

के लिए भी तात्कालिक चुनौती बन सकती है।

ट्रम्प द्वारा प्रवासी वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों पर की जा रही सख्ती

का जिक्र करते हुए सीएनएन ने एक प्रमुख चीनी वैज्ञानिक को उद्धृत किया, जो अब अपने देश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा, चीनी विश्वविद्यालय, एक

चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 29 सितम्ब। बीपन नदी के ऊपर 625 मीटर की ऊँचाई पर बना चीनी पुल जो अब दुनिया का सबसे ऊँचा पुल है, बन कर तैयार है, जो घाटी के पार यात्रा के समय को दो घंटे से घटाकर सिर्फ दो मिनट कर देता है।

चीन ने आधिकारिक रूप से

■ 625 मीटर ऊंचे पुल से यात्रा का समय 2 घंटे से घट कर 2 मिनट रह गया है।

“हुआजियांग ग्रैंड केन्यन ब्रिज” को जनता के लिए खोल दिया है। गुइझोउ प्रांत में स्थित यह अद्भुत वास्तुशिल्प संरचना, 625 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और चीन के सबसे कठिन भू-भागों में कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल देती है।

28 सितंबर को, लाइव ड्रोन फुटेज में देखा गया कि कैसे वाहन इस विशाल पुल को पार कर रहे थे, जिसके नीले स्पॉट टावर्स नीली सहायक बादलों में आंशिक रूप से छिपे हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने लिखी मैलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना

नयी दिल्ली, 29 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि “आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स” इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केवल आत्मकथा नहीं है, यह उनके "मन की बात" है। प्रधानमंत्री ने मेलोनी की आत्मकथा “आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स” की प्रस्तावना लिखते हुए कहा है, "भारत और इटली

■ प्र.मंत्री मोदी ने लिखा, यह इटली की प्र.मंत्री मैलोनी की आत्मकथा मात्र नहीं, बल्कि उनके “मन की बात है।”

संधियों या व्यापार से कहीं ज्यादा विरासत की रक्षा, समुदाय की मजबूती और नारीत्व को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में मानने जैसे साझे मूल्यों से बंधे हैं।” उन्होंने कहा कि दोनों देशों में परंपराओं के प्रति सम्मान और आधुनिकता को अपनाने की एक जैसी भावनाएं मौजूद हैं। मोदी ने इन साझे मूल्यों को अपनी और मेलोनी की व्यक्तिगत मित्रता का आधार बताया है।

उल्लेखनीय है कि इस आत्मकथा की भूमिका में मोदी के अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्रिकेट मैच के बाद भारत-पाक नेताओं में छिड़ी ज़ुबानी जंग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं

■ प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया कप फाइनल में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा और लिखा, “नतीजा वही रहा, भारत की जीत।”

■ इस पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने जवाब में लिखा, अगर युद्ध आपके गर्व का मानदंड था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों हुई आपकी अपमानजनक हार को दर्ज करता है।

■ सोशल मीडिया भी भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान दोनों टीमों के व्यवहार पर टीका टिप्पणियों से अटा पड़ा है।

उसने यह जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के छह विमान मार गिराए थे। इसी प्रकार, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया, जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने, उनके साथ फोटो खिंचवाने

और यहां तक कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने तक से इनकार कर दिया। नकवी मेडल और ट्रॉफी लेकर अपने होटल के कमरे में चले गए। कल वह अנוखा क्षण था, जब भारतीय टीम को बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाते

देखा गया। सवाल यह उठता है कि अगर रिस्ते इतने कड़वे और तनावपूर्ण हैं, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने का निर्णय किया ही क्यों था? इतिहासकार और खेल लेखक रामचंद्र गुहा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने खेल में राजनीति घुसाकर अपने पद की गरिमा कम कर दी और पाकिस्तानी नेताओं की संस्कृति के स्तर तक उतर गए। गुहा ने कहा कि भारत ने खेलने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि बीसीसीआई वित्तीय लाभ कमाना चाहता था।

गुहा की दलीलें पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। खेल और राजनीति परंपरागत रूप से अलग-अलग क्षेत्र रहे हैं और खेल भावना और आपसी सौहार्द की पवित्रता हमेशा बनाए रखी गई है। कुछ उदाहरण: सन् 1974 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेला था और यहां तक कि अंशभेद के खिलाफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी कोलंबिया पहुंचे

नयी दिल्ली, 29 सितंबर। दक्षिण अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर गये लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचे।

कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में हवाई अड्डे पर गांधी के

■ दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में राहुल छात्रों व व्यापारिक समुदाय से मिलेंगे।

स्वागत का एक वीडियो साझा करते हुए यह जानकारी दी।

पार्टी ने आगे कहा “गांधी कोलंबिया के बोगोटा पहुंचे। वे दक्षिण अमेरिका के दौर पर हैं, जहां उनका चार देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है।

पाक अधिकृत कश्मीर में न्याय की मांग अब पूर्ण बगावत का रूप ले चुकी है

हज़ारों की संख्या में उत्तेजित जनता सड़कों पर उतर आई हैं, कर्फ्यू व दबाने की कोशिशों के बावजूद

- सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली 29 सितम्बर। पाक ऑक्जुपाइड कश्मीर (पीओके) में तूफान उठ रहा है। वर्षों बाद पहली बार, हज़ारों नाराज नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं वो भी कर्फ्यू और दमन को नजरअंदाज करते हुए। अवामी एक्शन कमेट्री (एएससी) द्वारा शुरू की गई न्याय की अपील अब एक पूर्ण जनविद्रोह बन चुकी है - इस्लामाबाद द्वारा दशकों से की गई उपेक्षा और शोषण के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सरकार ने क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पीओके एक गहरे राजनीतिक संकट के कगार पर खड़ा है।

भारत, जो जम्मू-कश्मीर सहित पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है, के लिए ये विरोध एक रणनीतिक मोड़ है। यह असंतोष पाकिस्तान के उस पुराने दावे को झुटलाता है कि पीओके एक "संतुष्ट" इलाका है, यह आंदोलन इस्लामाबाद के नियंत्रण की आंतरिक कमजोरियों को भी उजागर करता है। नई दिल्ली इसे अपने रूख की पुष्टि के रूप में देखती है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर दावा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कि जब उसके खुद के कब्जे वाले इलाके ही असंतोष से उबल रहे हों, तो उसे कश्मीर मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। साथ ही, पीओके में अस्थिरता नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा जोखिम भी बढ़ा सकती है। पाक सरकार की सख्त कार्रवाई शरणार्थी संकट, सीमा पर तनाव या आंतरिक विद्रोह को बाहरी मोर्चे पर मोड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।

इस विद्रोह के केन्द्र में है पाकिस्तान

■ पाक का यह प्रचार, कि पीओके एक खुशनुमा और संतुष्ट प्रदेश है, अब खोखला साबित हो गया है।

■ इस समस्या से पाकिस्तान सरकार पुराने जाने-पहचाने तरीकों से निपटना चाहती है, दमन एवं अर्द्ध सैनिक बलों व सेना के इस्तेमाल से, यहाँ तक कि इंटरनैट व सोशल मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण करके एरिया को अलग-थलग कर आवाज़ों को अपनी मौत मार देना चाहती है।

■ यह बगावत सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, आम जनता सिविल सोसायटी और वकील आदि भी इसका मुखर समर्थन कर रहे हैं। मुज़फ्फराबाद के एक नामी वकील ने कहा है कि आंदोलन मतभेद जाहिर करने का यह प्रजातंत्रीय तरीका है और इसे सुना जाना चाहिए।

द्वारा क्षेत्र के लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखना। यह ऐसी भावना है, जो न केवल इस्लामाबाद की आंतरिक स्थिरता पर बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब नीलम घाटी सार्वजनिक एक्शन कमेट्री के नेता शौकत नवाज़ मीर ने पाक अधिकृत कश्मीर में अनिश्चितकालीन "शटर डाउन और चक्का जाम" हड़ताल की घोषणा की। उनका संदेश स्पष्ट था - वर्षों की उपेक्षा

भ्रष्टाचार और शोषण ने जनता को उबाल पर ला दिया है।

मुज़फ्फराबाद से मीरपुर तक, लोग अपने मूलभूत मानव अधिकारों की मांग कर रहे हैं - साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर स्वायत्तता जनता

का गुस्सा पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर भी है, जिसने कथित रूप से विकास के लिए मिले फंड हड़प लिए और असहमति को दमन के ज़रिए दबा दिया।

पाक अधिकृत कश्मीर की सरकार का आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का बयान आग में घी डालने जैसा रहा है। वकीलों और नागरिक समाज के संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है और इसे एक वैध लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बताया है। मुज़फ्फराबाद के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, जनता की मांगों को कुचला नहीं जाना चाहिए, बल्कि सुना जाना चाहिए। संवाद की बजाय इस्लामाबाद ने वही पुराना रास्ता चुना है - अर्धसैनिक रेंजर्स की तैनाती, इंटरनेट बंद करना, और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घाटी में अस्थाई रूप से बंद पर्यटन स्थल फिर से खुले

जम्मू, 29 सितंबर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को कश्मीर घाटी के उन सात प्रमुख पर्यटन स्थलों को दोबारा खोल दिया है, जिन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया था। यह निर्णय शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की

■ इसमें कश्मीर संभाग के सात व जम्मू के 5 क्षेत्र शामिल हैं। इन्हें पहलगाम के अटक के बाद बंद कर दिया गया था।

अध्यक्षता में हुई यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बैठक के बाद लिया गया। आज यूएचक्यू की बैठक में सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा और चर्चा के बाद, जम्मू और कश्मीर डिवीजनों में अस्थायी रूप से बंद किए गए कई पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

